जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

उदयपुर

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

फोनः- 2418945 फैक्सः- 0294-2410146 वर्षः 30 संख्याः 137 प्रभात उदयपुर, मंगलवार 21 मार्च, 2023 आर.जे. 7202 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

गुजरात में शेरों के संरक्षण के प्रयास इतने ज्यादा सफल हुए हैं कि, शेरों की बढ़ी हुई आबादी को एडजस्ट करने के लिए एक नया अभयारण्य बनाना पड़ेगा। गुजरात का गीर नैशनल पार्क एशियाटिक लायन प्रजाति का एकमात्र घर है तथा अफ्रीका के बाद गीर ही एकमात्र जगह है जहां शेर देखे जा सकते हैं। इस संकटग्रस्त जीव की संख्या अब काफी बढ़ गई है। गीर में 400 शेर हैं तथा गुजरात के अन्य भागो में तीन सौ। गीर में शेरों की आबादी जरुरत से ज्यादा है। जगह की कमी की वजह से शेर गांवों व तटवर्ती क्षेत्रों का रुख करते हैं। संरक्षणविद् गुजरात सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि, शेरों को यहाँ से भारत में अन्य स्थानों पर भेजा जाए ताकि गीर में जो शेर बचे हैं उन्हें पर्याप्त जगह मिल सके। एक ही जगह पर एक ही प्रजाति के बहुत सारे सदस्य हों तो संक्रमण का खतरा बहुत बढ़ जाता है, लेकिन राज्य सरकार इस मांग का विरोध कर रही है। आलोचकों का कहना है कि, गुजरात सरकार शेरों पर एकाधिकार चाहती है और उनके हितों की अनदेखी कर रही है। गुजरात सरकार ने वर्ष 2013 के सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की भी अवहेलना की कि, कुछ शेरों को मध्य प्रदेश के अभयारण्यों में भेजा जाए। आदेश में कहा गया था कि, शेरों को संक्रमण से बचाने के लिए ऐसा करना जरुरी है। अब जाकर गुजरात सरकार ने कहा है कि, गीर से कुछ शेर दूसरे स्थान पर भेजे जाएंगे। हालांकि यह जगह, "बरडा वाइल्डलाइफ सैंचुरी" भी गुजरात में ही है। इस नए घर में 40 शेर भेजे जाएंगे और इसकी तैयारी चल रही है। वाइल्ड लाइफ कंज़र्वेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष अनीश अंधेरिया का कहना है कि गुजरात सरकार फिर गुमराह कर रही है, वह अन्य राज्यों को शेर देना ही नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि गीर व गुजरात के अन्य स्थानों के शेर पहले ही जगह की तलाश में बरडा पहुंच चुके हैं। अंधेरिया ने कहा कि, नए शेर अभयारण्य के रुप में बरडा के नाम की औपचारिक घोषणा से क्षेत्र को बेहतर फंड और बेहतर प्रबंधन मिल सकता है पर इससे गीर का दबाव कम नहीं होगा। उन्होंने कहा, भारत में शेरों की संख्या बढ़ना अच्छी खबर है पर बेहतर होगा अगर शेरों को देश के अन्य भागों में भी भेजा जाए, इसी से गीर व गुजरात के शेरों को पर्याप्त जगह मिल सकेगी।

'अभी तक 25 सितम्बर के प्रकरण की पूरी जांच क्यों नहीं हुई'

पायलट ने न्यूज 18 के चौपाल प्रोग्राम में यह सवाल कि, 25 सितम्बर को मु.मंत्री गहलोत ने हाई कमान के खिलाफ बगावत की थी तथा विधायक दल की बैठक नहीं होने दी थी, पर, इस पूरे प्रकरण में अभी तक अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों नहीं हुई?

- उन्होंने कहा, इसी प्रकार विधानसभाध्यक्ष सी.पी. जोशी ने बताया था कि, उन्होंने विधायकों के इस्तीफे इसलिये स्वीकार नहीं किये, क्योंकि वे दबाव में दिये गये थे। पर, आज तक यह जांच नहीं हो सकी कि, किसका दबाव था और दबाव लगाने वाले के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गयी।
- दिग्विजय सिंह ने इस प्रकरण में टिप्पणी की थी कि, अगर पायलट को कोई शिकायत है या पीड़ा है, तो वे अनुशासन समिति के समक्ष जाते। पायलट ने इस बारे में चौपाल में कहा, ए.के. एंटनी की अध्यक्षता में गठित अनुशासन समिति ने इस प्रकरण में ''नोटिस'' भी जारी किये, तीन आरोपियों को, उनके जवाब भी आये, पर अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई।
- पायलट ने यह सवाल भी उठाया कि, उनके व महासचिव अजय माकन के बार-बार कहने के बाद भी, छः महीने बीत जाने के बाद भी विधायक दल की बैठक क्यों नहीं आहूत की गयी।

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 मार्च। कांग्रेस नेतृत्व को कठघरे में खड़ा करते हुए, राजस्थान के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने 25 सितम्बर की घटनाओं की जाँच की मांग की है, जब अशोक गहलोत ने कांग्रेस के नेतृत्व के विरूद्ध विद्रोह कर दिया था।

सचिन पायलट जानना चाहते थे कि, पार्टी ने इन्क्वायरी क्यों नहीं की, जब विधानसभा स्पीकर सी.पी. जोशी ने कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे यह कहकर खारिज कर दिए कि, इस्तीफे दबाव में आकर दिए गए थे।

सचिन ने पूछा है कि, यह क्या दबाव था, किसका दबाव था और पार्टी नेतृत्व ने यह जानने का प्रयास क्यों नहीं किया कि, उस दिन हुआ क्या था।

दिग्विजय सिंह के इस सुझाव पर प्रश्न पूछे जाने पर कि, यदि पायलट को कुछ शिकायतें हैं तो उन्हें अनुशासन समिति के समक्ष जाना चाहिए, पायलट ने ए.के. एन्टनी की अध्यक्षता वाली अनुशासन समिति को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि, राजस्थान में उन तीन लोगों को नोटिस जारी किए गए थे, उनके जवाब भी आएं, लेकिन अभी तक संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

अशोक गहलोत द्वारा सचिन पायलट के लिए गद्दार जैसे शब्दों का प्रयोग करने के मुद्दे पर सचिन पायलट ने कहा, यह उनकी संस्कृति, संस्कार शिक्षा है। उन्होंने कहा, उनकी (पायलट की) परवरिश ऐसी नहीं हुई है कि, अपने से बड़ों को अपशब्द कहें, क्योंकि, एक बार मुँह से निकलने के बाद शब्द वापस नहीं लिए जा सकते।

पायलट ने कहा, यह निर्णय तो नेतृत्य को लेना है कि, पार्टी का नेता कौन होगा, और जहाँ, उन्होंने पार्टी को सत्ता में लाने के लिए पाँच साल काम किया, वरिष्ठ नेताओं सहित सभी नेताओं को साथ में लेकर, वहीं पार्टी नेतृत्व ने गहलोत को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय लिया।

(शेष पृष्ठ 5 पर)

क्या आपको कम सुनाई देता है।
कान की मशीनें
स्पीच थैरेपी
फ्री सुनाई की जाँच
TRIAL OF HEARING AID
CALL FOR APPOINTMENT
+91 94602 07080
PERFECT SPEECH AND HEARING SOLUTIONS
Tonk Road, JAIPUR | Vaishali Nagar, JAIPUR
www.perfecthearingsolutions.com

'चीन के ''नैटिज़न'' भारत की तुलना में पाकिस्तान की ओर झुकाव को अव्यवहारिक मानते हैं'

इन ''नैटिज़न्स'' का मानना है कि, पाकिस्तान व भारत में ''गैप'' बहुत बड़ा हो गया है और बढ़ता ही जा रहा है

- इन लोगों का इस प्रश्न का भी अजीबोगरीब जवाब है कि, भारत क्यों पाश्चात्य देशों का प्रिय होता जा रहा है, जबकि चीन पाश्चात्य देशों के निशाने पर है।
- नैटिज़न्स का इस बारे में मानना है कि, भारत इतना विकसित नहीं है कि, भारत पाश्चात्य देशों को चुनौती देने की स्थिति में हो। अतः वे भारत को अपने लिये कोई खतरा नहीं मानते, जबकि विकसित व सक्षम होने के कारण ये देश चीन से आशंकित महसूस करते हैं।
- ये नैटिज़न्स, प्र.मंत्री मोदी से भी काफी प्रभावित हैं तथा वे मानते हैं, भारत के प्रधानमंत्री मोदी विश्व के देशों में बड़ी होशियारी से संतुलन बिठाकर रखते हैं, जो बहुत प्रशंसनीय है।

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 मार्च। चीन-भारत के बीच चल रहे सीमा विवाद के बावजूद चीन की जनता की भारत के विरूद्ध कोई दुर्भावना नहीं है। वास्तव में वहां की जनता महसूस करती है कि भारत की सत्ता एक ऐसे नेता के हाथ में है जो विश्व की अन्य शख्सियतों से आश्चर्यजनक रूप से भिन्न है और दोनों देश मित्र बन सकते हैं।

चीन में सोशल मीडिया पर अधिक समय बिताने वाले लोगों का कहना है कि मोदी के नेतृत्व वाला भारत विश्व के बड़े देशों के बीच संतुलन स्थापित कर सकता है। चाहे वह रूस हो, अमेरिका हो या ग्लोबल साउथ कंट्रीज़, भारत इन सभी के साथ दोस्ताना संबंध रख सकता है।

चीन के मीडिया में मोदी की प्रशंसा की भरमार है। उसने उन्हें एक असाधारण उपनाम ''मोदी लाओक़िज़यान'' दिया है। लाओक़िज़यान का तात्पर्य एक बुजुर्ग अविनाशी व्यक्ति से है, जिसमें कुछ विलक्षण क्षमताएं हैं। यह उपनाम संकेत देता है कि चीन में सोशल मीडिया के आदी लोग ऐसा सोचते हैं कि मोदी अन्य नेताओं से अलग और यहां तक कि अधिक आश्चर्यजनक हैं। वे उनकी ड्रैस और शारीरिक उपस्थिति दोनों को एक लाओक़िज़यान की भांति देखते हैं और उनकी कुछ नीतियां भारत की पूर्व नीतियों से अलग है। अतः ''लाओक़िज़यान'' शब्द मोदी के प्रति चीन के लोगों की मिश्रित भावनाओं को परिलक्षित करता है, जिसमें जिज्ञासा, आश्चर्य और शायद नक चढेपन का समावेश है। चीन में सोशल मीडिया पर अधिक समय बिताने वाले लोगों के विचारों का संकलन बीजिंग के पत्रकार क्यू चुन्शान ने किया है और इन्हें प्रकाशित किया है वॉशिंगटन की एक इन्टरनैशनल ऑनलाइन न्यूज़ मैगज़ीन ''द डिप्लोमैट'' ने।

क्यू चीन के शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से चलने वाले एक रिसर्च प्रोजैक्ट का हिस्सा रह चुके हैं। इस प्रोजैक्ट के तहत चीन की छवि निर्मित करने में विदेशी मीडिया के प्रभाव की जांच की गई थी। वह लिखते हैं कि ''मैं करीब 20 वर्षों से इन्टरनैशनल मीडिया रिपोर्ट्स पर काम करता आया हूँ, चीन के सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले लोगों द्वारा किसी विदेशी नेता को

(शेष पृष्ठ 5 पर)

सत्तारूढ़ पार्टी ने छठे दिन भी संसद नहीं चलने दी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 मार्च। संसद के दोनों सदन बजट सत्र के दूसरे हिस्से के छठे दिन, सोमवार को भी स्थगित कर दिये गये क्योंकि सत्तारूढ़ भाजपा सदस्य राहुल गांधी द्वारा माफी माँगे जाने के लिये नारेबाजी कर रही थी, शोर-शराबा कर रही थी तथा उधर विपक्ष भी अडानी प्रकरण की जाँच के लिये जॉइन्ट

- दोनों ही सदन पहले दो बजे तक के लिए स्थगित किए गए थे, फिर पूरे दिन के लिए संसद की कार्यवाही स्थगित कर दी गई।

पॉर्लियामैन्ट्री कमेटी (जे.पी.सी.) की माँग पर अड़ा हुआ था।

दोनों सदन पहले अपरान्ह 2 बजे तक के लिये तथा उसके बाद, वैसे ही परिदृश्य के चलते, दिनभर के लिये स्थगित कर दिये गये।

गत पूरे सप्ताह भी यही दोनों सदनों का आलम रहा था।

हालाँकि शोर-शराबा दोनों ही पक्षों

(शेष पृष्ठ 5 पर)

'बंद लिफाफों में इन्फॉर्मेशन देना बंद कीजिये'

मुख्य न्यायाधीश ने एटॉर्नी जनरल को झाड़ पिलायी

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 मार्च। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाय. चन्द्रचड़ ने आज अदालतों में ''सीलबंद लिफाफा व्यवस्था'' का सहारा लेने के चलन पर कड़ा ऐतराज़ जताया तथा एटॉर्नी जनरल द्वारा प्रस्तुत किये गये सीलबंद लिफाफे को स्वीकार करने से इंकार कर दिया। उन्होंने सरकार के सर्वोच्च वकील से कह दिया कि वे या तो इसे पढ़ें या फिर वापस ले जायें।

वन रैंक वन पेंशन (ओ.आर.ओ.पी.) केस की सुनवाई करते समय, मुख्य न्यायाधीश ने अदालतों में पेश किये जाने वाले सीलबंद लिफाफों के प्रयोग के चलन की घोर भर्त्सना की। उन्होंने भारत के अटॉर्नी जनरल द्वारा पेश किये गये उस सीलबंद लिफाफे को स्वीकार करने से इंकार कर दिया, जिसमें पेंशन के भुगतान को लेकर रक्षा मंत्रालय का निर्णय प्रेषित

- सुप्रीम कोर्ट के मु. न्यायाधीश का कहना था कि, यह एक न्यायालय है, अतः पूर्ण पारदर्शिता अनिवार्य है। अतः बंद लिफाफे में जो जानकारी मुझे आप देना चाहते हैं या तो उसे पढ़ कर सबके समक्ष सुनाएं या लिफाफा वापस ले जायें।

(शेष पृष्ठ 5 पर)

'लिव इन रिलेशनशिप्स के रजिस्ट्रेशन की याचिका गैर जिम्मेदाराना'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 मार्च। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को जनहित याचिका में ''गैर जिम्मेदाराना'' बताते हुये खारिज कर दिया, जिसमें लिव-इन-रिलेशनशिफ के रजिस्ट्रेशन की मांग की

- सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने लिव इन रिलेशनशिप्स के रजिस्ट्रेशन के लिए दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि, ''लोग कुछ भी लेकर आ जाते हैं, लोग लिव-इन रिलेशनशिप में रहते हैं उसमें केन्द्र सरकार क्या करेगी।''

गई थी। अदालत ने कहा कि इस प्रकार के सम्बंध के लिये कोई नियम या गाइडलाइनें नहीं हैं।

मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चन्द्रचूड़

(शेष पृष्ठ 5 पर)

सिलिकॉन वैली बैंक को डूबने से बचाने के लिये अमेरिका ने ''पवित्र व पावन'' इकोनॉमिक सिद्धांत तोड़ दिये

अमेरिका का तर्क था, ''पवित्र व पावन'' सिद्धांतों का समय नहीं है, ''व्यवहारिक इकोनॉमिक्स'' का वक्त है

- पर, जब एशिया या अन्य ''थर्ड वर्ड'' के देश (जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका आदि) अपने ऋण चुकाने में सफल नहीं हो रहे तो, आई.एम.एफ. व अन्य अमेरिका द्वारा संचालित व नियंत्रित अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, बहुत ही कड़े व शर्मिन्दा करने वाले नियम-कायदों की बात कर रहे हैं।
- आशा है इस ''रियल इकॉनमी'' (व्यवहारिक अर्थ नीति) में सामयिक रद्दोबदल से भारत भी कुछ सीखेगा।
- ''फिस्कल प्रूडैन्स'' इकॉनमी के सभी बैंकिंग नियम कायदों की पूर्ण क्रियान्विति के चक्कर में भारत के वित्त मंत्री ने इतने सख्त ''ब्रेक'' लगा दिये थे कि, पूरी इकॉनमी ही चरमरा कर रूक सी गयी थी।
- छोटा सा उदाहरण है, सिलिकॉन वैली बैंक के मामले में अमेरिका ने सार्वजनिक घोषणा की कि, डिपॉजिटर्स को सारा पैसा तुरंत मिलेगा, जब वे बैंक से पैसा निकालने जायेंगे। आम तौर पर बैंक के फेल होने की संभावना में इंश्योरैंस के नियम एक सीमा बांध देते हैं कि, डिपॉजिटर को कितना पैसा मिलेगा तुरंत। इससे घबराहट पैदा होती है तथा डिपॉज़िटर भगदड़ मचा देते हैं, पैसा निकालने की होड़ में। पर, अगर उसे पूरे पैसे मिलने की गारंटी तुरंत मिलने की सरकारी घोषणा होती है, तो पैसा निकालने वालों की भगदड़ अपने आप खत्म हो जाती है।
- क्या हिन्दुस्तान से कम से कम बैंक ऐसी घोषणा नहीं कर सकते, संकट के समय?

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 मार्च। अमेरिका के नीति निर्माताओं ने संकटों से घिरे सिलिकॉन वैली बैंक को संकट से उबारने के तुरत-फुरत कदम उठाए।

रीयल पॉलीटिक के समानांतर ''रीयल इकोनॉमिक्स'' की संज्ञा दी जा सकती है। रीयल-पॉलीटिक वास्तविक अर्थों में राजनीति करने की कला है और उसी तरह से रीयल इकोनॉमिक्स आर्थिक मुद्दों से वास्तविक तरीके से निबटना है। वर्ष 2007-2009 की वैश्विक वित्तीय मंदी के बाद हमने निश्चित रूप से इसके कुछ उदाहरण देखे हैं, लेकिन 14 वर्ष बाद यह सारी स्मृति कमजोर हो गई है।

साधारण अर्थों में यह किसी आर्थिक आपातकाल से कथित मुक्त व्यापार के दृढ़ सिद्धान्तों के बजाए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण रखकर निबटना है।

मुक्त व्यापार अर्थव्यवस्था के मक्का माने जाने वाले अमेरिका में ऐसे उच्च सैद्धान्तिक मापदण्डों का कई बार उल्लंघन होता आया है, जिसमें इसे मानने वालों ने विकासशील देशों की उनके संकट के समय में सहायता की जिसे वॉशिंगटन सर्वानुमति'' के नाम से जाना गया।

वॉशिंगटन सर्वानुमति ने आर्थिक संकट का सामना कर रहे देशों को ऋण देने के लिए मितव्ययता बरतने की शर्तें रखीं। उदाहरण के तौर पर हाल ही कुछ देश चीन से विशालकाय ऋण लेने के बाद एक तरह से दिवालिया हो गए हैं। इन देशों पर यह दबाव डाला जा रहा है कि वे मितव्ययता के व्यापक उपाय करें।

तथापि, पिछले गुरुवार को जब सिलिकॉन वैली बैंक के जमाकर्ताओं ने अपनी रकम निकालनी शुरु की तब अमेरिका के केन्द्रीय बैंक और अमेरिकी सरकार ने इसके डूबने के प्रति उदासीन

(शेष पृष्ठ 5 पर)

दिल्ली में किसानों की विशाल रैली, एक और आंदोलन की चेतावनी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 मार्च। हजारों की संख्या में किसान सोमवार को संसद भवन से 5 किमी दूर स्थित रामलीला

- संसद भवन से 5 किलोमीटर दूर रामलीला मैदान में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों की बड़ी सभा हुई, बाद में किसानों ने केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा।

मैदान में एकत्रित हुये तथा उन्होंने धमकी के स्वर में कहा कि अगर सरकार ने उनकी माँगे, जिनमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस (एम.एस.पी.) को लेकर कानून,

(शेष पृष्ठ 5 पर)